



हिन्दी दैनिक



जोहार

रांची संस्करण

www.tezraftarlive.com
Email-navbiharjh@gmail.com

प्रत्युष नवविहार

रांची, पटना और दिल्ली से प्रकाशित

रांची • बुधवार • 09.10.2024 • वर्ष : 15 • अंक : 80 • पृष्ठ : 12 • आमंत्रण गूल्य : ₹ 2 रुपये

हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के हाथ सता की चाबी

एजेंटी

नयी दिल्ली : जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉर्फ़ेस (एनसी) और कांग्रेस के गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बहुमत हासिल किया है। वहाँ भाजपा ने हरियाणा में सता विरोधी लहर को लेकर राजनीतिक पड़ितों के अनुमतियों को धता बताते हुए लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है। चुनाव आयोग के अनुसार जम्मू-कश्मीर के चुनावी नीतियों में एनसी को 42, भाजपा को 29, कांग्रेस को 06, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी 03, जम्मू-कश्मीर पीपल सार्कसावादी क्यानिस्ट पार्टी और आम आदिम पार्टी को एक-एक सीटें मिली हैं। जबकि उमर अब्दुल्ला ने निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। नीतीजों से



जीती हैं। राज्य में सरकार बनाने के लिए 46 का आंकड़ा चाहिए। एनसी और कांग्रेस के गठबंधन को कुल 48 सीटें मिली हैं। राज्य में 10 साल बाद हुए चुनाव में एनसी-कांग्रेस गठबंधन की सरकार बननी तय मानी जा रही है। दूसरी ओर हरियाणा विधानसभा चुनाव के नवीनी पूरी तरह से अप्रत्याशी रहे। तमाम एपिट पोल और एंटी-सीटों के दावों को धता बताते हुए इस बार भी भाजपा राज्य में सरकार बनाने जा रही है। भाजपा को 90 सदस्यीय विधानसभा के चुनावी नीतियों में एनसी को 42, भाजपा को 29, कांग्रेस को 06, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी 03, जम्मू-कश्मीर पीपल सार्कसावादी क्यानिस्ट पार्टी और आम आदिम पार्टी को एक-एक सीटें मिली हैं। तीन सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। नीतीजों से

राज्य में भाजपा की सरकार बननी तय है। राज्य की धता बताते हुए इस बार भी भाजपा राज्य में सरकार बनाने जा रही है। भाजपा को 90 सदस्यीय विधानसभा में 48 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस को 37, ईडिवन नेशनल लोक दल को दो सीटें मिली हैं। तीन सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। नीतीजों से

मिले हैं और उसके बाद एनसी को 23.43 प्रतिशत मत मिले हैं। कांग्रेस को यहाँ 11.97 प्रतिशत वोट मिले हैं। दूसरी ओर हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस का मत प्रतिशत के हिसाब से भाजपा जम्मू-कश्मीर में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाली पार्टी बनी है। भाजपा को 39.94 प्रतिशत और कांग्रेस को 39.09 प्रतिशत वोट मिले हैं। भाजपा को 25.64 प्रतिशत वोट कोई कांग्रेस-कांग्रेस नहीं छींगे।

हरियाणा की जीत विकास और सुशासन की राजनीति की जीत : प्रधानमंत्री



नयी दिल्ली : भाजपा के विरियों नेता एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हरियाणा विधानसभा चुनावों में मिली जीत का सुशासन की राजनीति की जीत बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी नीतीजों के बाद एक बार के दावों को धता बताते हुए इस बार भी भाजपा राज्य में सरकार बनाने जा रही है। भाजपा को 90 सदस्यीय विधानसभा के चुनावी नीतियों में एनसी को 42, भाजपा को 29, कांग्रेस को 06, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी 03, जम्मू-कश्मीर पीपल सार्कसावादी क्यानिस्ट पार्टी और आम आदिम पार्टी को एक-एक सीटें मिली हैं। तीन सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। नीतीजों से

जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना हमारी प्राथमिकता : जयराम



नयी दिल्ली : जम्मू-कश्मीर के चुनावी नीतीजों के बाद कांग्रेस ने कहा है कि प्रदेश का पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना उसकी प्राथमिकता होगी। जम्मू-कश्मीर की 90 सदस्यीय विधानसभा में नेशनल कॉर्फ़ेस और कांग्रेस गठबंधन ने 48 सीटें जीती हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रेशम और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मगलवार को पार्टी की जनशक्ति को नमन करते हैं। यह विकास और सुशासन की राजनीति की जीत है। वे यहाँ के लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि उनकी आकाशकांशों को पूरा करने के लिए कोई कांग्रेस-कांग्रेस नहीं छींगे।

जम्मू-कश्मीर का मुख्यमंत्री बनकर परिवार की विसरात आगे बढ़ाने को तैयार : उमर



श्रीनगर : नेशनल कॉर्फ़ेस के पार्टी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बड़गाम में प्रभावशाली जीत हासिल करने के बाद कहा है कि वह जम्मू-कश्मीर का मुख्यमंत्री बनकर अपने परिवार की विसरात को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। कुछ महीने पहले ही अब्दुल्ला को लोकसभा चुनावी में शर्मनाक हार का समाप्त करना पड़ा। फालूका अब्दुल्ला ने घोषणा की कि उनके बेटे उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 41 सीटों पर आगे चल रही जेंडरनी सहायी कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

हेमन्त सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में आयोजित समारोह में 76 नवनियुक्तों को सौंपा नियुक्ति पत्र

सरकार का पहिया बनकर राज्य के सर्वार्गीण विकास ने निभाएं अहम भूमिका : मुख्यमंत्री

प्रत्युष नवविहार संवाददाता

रांची : नौजवानों को नियुक्त पत्र, प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्पादन, उत्कृष्ट शिक्षा में विश्वास एवं विद्यालयों का अलंकरण और नेतरहार विद्यालय की तर्ज पर तीन नए विद्यालयों का शिलान्यास। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा ज्ञारखंड में आयोजित समारोह में एक बार फिर एक साथ कई सार्वजनिक देकर शिक्षा के क्षेत्र में एक और मिसाल कायम की।

मुख्यमंत्री ने प्रतिभावान विद्यार्थियों का उत्साह और जनोबल बढ़ाया

मुख्यमंत्री ने समारोह में 76 नवनियुक्तों को नियुक्त पत्र सौंपा। इनमें ज्ञारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में 35 लें-एजीवीयूटिक, 4 एनीजीवीसीएस इंजीनियर, 21 अर्सिस्टेंट इंजीनियर और 10 स्कूल मैनेजर तथा ज्ञारखंड भवन नई दिल्ली तथा ज्ञारखंड भवन में विकास करने वाले अव्याधियों से कहा कि आज से आप सरकार के एक अधिनन अंग के रूप में जुड़ रहे हैं। राज्य के सर्वार्गीण विकास का पहिया आप बन रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास



आप राज्य के सर्वार्गीण विकास का पहिया बन रहे हैं

परीक्षा और ज्ञारखंड ओलीपियाड - 2023 के टॉपर्स को सम्मानित कर उनके हौसले, उत्साह और मोबाल को बढ़ाते हुए उत्ज्ञल भवित्व के दावों के क्षेत्र के रूप में विकास करने के लिए एक सार्वजनिक देकर विद्यालय द्वारा दिया गया, जब युख्यमंत्री ने नियुक्त पत्र प्राप्त करने वाले अव्याधियों से कहा कि आज से आप सरकार के एक अधिनन अंग के रूप में जुड़ रहे हैं। राज्य के सर्वार्गीण विकास का पहिया आप बन रहे हैं।

परीक्षा और ज्ञारखंड ओलीपियाड को बेहतर दिशा देने में अहम भूमिका निभाएं।

वार्षिका के स्कूलिंगी, बोकारो के नवाईही और दुमका के मसलिया में तीन विद्यालयों का किया ऑनलाइन शिलान्यास।

► जैक, सीबीएसई, आईसीईसई की 10 वीं तथा 12 वीं बोर्ड परीक्षा एवं ज्ञारखंड ओलीपियाड के टॉपर्स को किया सम्मानित।

► विद्यालय प्रमाणीकरण ने स्वर्ण प्राप्त करने वाले विद्यालयों को भी मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित।

राज्य के रूप में ज्ञारखंड की अलग पहचान बने, चाहे वह शिक्षा हो या खेल या कोई और क्षेत्र। सरकार शिक्षा के समर्थनकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं।

पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना का दायरा बढ़ाने पर स्वरक्कार जल्द लेनी नीतिगत निर्णय

मुख्यमंत्री ने कहा कि मरांग गोमके जयागां परियोजने के लिए मुंदा पारेरीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत सरकार के अधिकारी ने कहा कि योजना के लिए विद्यार्थियों के ज्ञानावधि विकास के लिए विद्यार्थियों में उच्च शिक्षा विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यालयों को इसका लाभ देंगे। अपनी इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों की संख्या से मेधावी विद्यार्थियों को करते हुए कहा कि आज पुरुषकर नहीं प्रोत्साहन राशि मिल रहा है। ताकि, आप आप अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें वहले इसका दायरा काफी बढ़ायें। लेकिन, अब इसमें जीती बोर्ड के टॉपर्स को भी शामिल करने की संख्या बढ़ायें।

वार्ड के टॉपर्स को भी शामिल करने की संख्या बढ़ायें।

परीक्षा के रूप में ज्ञारखंड की अंतर्गत सरकार के अधिकारी ने कहा कि योजना के लिए विद्यार्थियों की संख्या बढ़ायें। अपनी योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों की संख्या बढ़ायें। अपनी योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों की संख्या बढ़ायें।

इसके लिए



उमीश चतुर्वदी

भारतीय जनता पार्टी ने
अगस्त 2019 में
अनुच्छेद 370 को
निष्प्रभावी करके एक
तरह से इस नायूर को
ही खत्म कर दिया। ऐसे
में इसका चुनावी श्रेय
भारतीय जनता पार्टी को
मिलने की उम्मीद होना
स्वाभाविक है। लेकिन
विधानसभा चुनाव
नतीजों ने पार्टी को
निराश ही किया है।

ज मूँ और कश्मीर राज्य एवं राम मंदिर में क्या कोई समानता हो सकती है? योटे तौर पर देखें तो इनमें कोई समानता नहीं हो सकती। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में दोनों को ही देखें तो समानता नजर आती है। राममंदिर और जम्मू-कश्मीर, भारतीय जनता पार्टी के कार मुद्दे रहे हैं। लेकिन चुनावी मोर्चे पर दोनों ही मुद्दे कम से कम स्थानीय स्तर पर भाजपा को निराश ही करते रहे हैं। सविधान के अनुच्छेद 370 और कैबिनेट के प्रस्ताव 35 ए की वजह से जम्मू-कश्मीर की स्थिति देश के अन्य राज्यों से अलग रही है। वह अलग स्थिति ही वहाँ के अलगाववाद की नासूर का कारण मानी जाती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करके एक तरह से इस नासूर को ही खत्म कर दिया। ऐसे में इसका चुनावी श्रेय भारतीय जनता पार्टी को मिलने की उम्मीद होना स्वाभाविक है। लेकिन विधानसभा चुनाव नतीजों ने पार्टी को निराश ही किया है। वहाँ पर राममंदिर आंदोलन और उस बीच हप्त उत्तर प्रदेश

वहाँ पर रामभादर अदालतन आर उस बायप हुए उत्तर प्रदेश के चुनावों की याद आना स्वाभाविक है। छह दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद अच्छल तो होना चाहिए था कि आगामी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर भारी जीत मिलती। लेकिन 1993 के विधानसभा चुनावों में भाजपा सबसे बड़ा दल बनकर भले ही उधरी, लोकेन वह बहुमत से दूर रही। जनवरी 2024 में अयोध्या में भव्य राममंदिर बनकर तैयार हो गया। देश और दुनिया में राममंदिर को लेकर अलग तरह का उत्साह देखा गया। पांच सौ वर्षों के संघर्ष का अंत हुआ। इस संघर्ष की अमृआ भारतीय जनता पार्टी ही रही। इसलिए इस संघर्ष का उसे चुनावों में फायदा मिलना चाहिए था। लेकिन उलटबांसी देखिए कि कुछ ही महीनों बाद हुए लोकसभा चुनावों में अयोध्या वाली फैजाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। इस कड़ी में कोर मुद्रे से जुड़े इताके जम्मू-कश्मीर में बीजेपी को चुनावी बढ़त ना मिलना, पार्टी के लिए तीसरा झटका कहा जा सकता है।

जम्मू-कश्मीर के चुनावी नतीजों के निहितार्थ



गठबंधन को बहुमत मिला है, उसका चुनावी बाद है कि राज्य की परानी स्थिति बहाल करेंगे यानी अनुच्छेद 370 को फिर से प्रभावी बनाएंगे। यह बात और है कि इस महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बहाली जम्मू-कश्मीर की आधी-अधूरी विधानसभा के बेश की बात नहीं है। लेकिन इस जीत के जरिए नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस नैतिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने की कोशिश तो ज़रूर ही करेगी। इसका उसे राष्ट्रीय फायदा भले ही न मिले, लेकिन केंद्रीय सत्ता पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परेशानी खड़ी करने का जरिया वे बनाने रहेंगे। वैसे भी भारत की राजनीति आज जिस मुकाम पर है, उसमें राजनीतिक दलों को सिफ़ अपने सियासी स्वार्थ और फायदे की चिंता है। उनकी प्राथमिकता में राष्ट्र बाद में आता है। इसलिए अंदरूनी मुद्दों को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उछलने में दलों को काहिं हिचक नहीं होती। विपक्ष के नेता साहुल गांधी के लंदन और अमेरिका के भाषण इसके उदाहरण हैं।

पाकिस्तानी मंशा को ही आगे बढ़ाते रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में भाजपा की चुनावी जीत ना मिलने के बाद वे फिर भाजपा के नजरिए को गलत साबित करने की कोशिश करेंगे।

जम्मू-कश्मीर के चुनावी अधियान के दौरान विशेषकर कश्मीर घाटी के बोटों के जो विचार सामने आ रहे थे, उससे ऐसे ही चुनाव नतीजों की उम्मीद थी। जिस घाटी में पत्थरबाजी रुक गई, जहाँ आंतकी घटनाओं पर लगाम लग गई, जहाँ ढाई दशक से पहले की तरह पर्टटों की अपमद बढ़ी, जहाँ अमन बढ़ा, वहाँ के लोग खुलाकर कहते रहे कि उन्हें हिंदू राज नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली सरकार की वजह से उन्हें ये सारी सहूलियतें मिलीं, राज्य में बदलाव आया। विकास की नई बवार बही। फिर घाटी के लोगों को ना तो नरेंद्र मोदी पसंद हैं और ना ही भारतीय जनता पार्टी। फिर कश्मीर घाटी में नवगठित विधानसभा की 47 सीटें आती हैं, जबकि जम्मू इलाके में 43 सीटें हैं। घाटी की सीटों पर भाजपा की चुनावी संभावनाओं की कोई उम्मीद भी नहीं लगाए हुए था। वैसे भी घाटी की 28 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार भी नहीं दिया थे। जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय का आंदोलन जिस प्रजा मंडल ने चलाया, उसका आधार जम्मू इलाके में ही रहा। वह एक तरह से भाजपा के पूर्ववर्ती जनसंघ का ही हिस्सा था। देश मान कर चल रहा था कि जम्मू इलाके की 43 सीटों में ज्यादातर पर बीजेपी की जीत होगी। लेकिन वहाँ बीजेपी 29 सीटें ही जीत पाई। जाहिर है कि 14 सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा। वैसे बीजेपी का एक घड़ा भान रहा है कि पार्टी की आपसी गुटबाजी और गलत टिकट बंटवारा पार्टी की सफलता की राह में बाधा बन गया। वैसे पार्टी के लिए संतोष की बात यह भी है कि घाटी की कई सीटों पर उसके उम्मीदवार हजार-दोहजार बोटों के ही अंतर से हारे हैं... फिर भी बीजेपी को सोचना होगा कि आखिर उससे चूक कहाँ हुई कि अपने गढ़ में वह शत-प्रतिशत सफलता हासिल कर्यों नहीं कर पाई। वैसे बीजेपी इस बात से राहत की सांस ले सकती है कि हरियाणा में वह धमाकेदार जीत के साथ वापस लौट रही है।

हरियाणा ने भी चला मोटी की करिएमाई लोकप्रियता का जादू



का दावा कर सके रह थे। मतदान संपन्न होने के बाद तो कांग्रेस को इतने अतिआत्मविश्वास ने जकड़ लिया था कि उसके अंदर नये मुख्यमंत्री के नाम पर भी विचार विमर्श प्रारंभ हो चुका था। मतगणना के दिन सुबह भी पार्टी के अंदर इसी तरह की चर्चाएँ चल रही थीं लेकिन दो तीन घंटे की मतगणना के बाद सभी कांग्रेस नेताओं के चेहरों का रंग फीका पड़ने लगा। एकिंजट पोल के नतीजों पर आंख मूंद कर भरोसा करना उन्हें महांग पड़ा। काश कांग्रेस के नेताओं ने एक बारगी यह भी सोच लिया होता कि एकिंजट पोल के नतीजे जिस तरह अतीत में भी कई बार गलत साबित होते रहे हैं उसी तरह इस बार भी गलत साबित हो गये तो पार्टी को कितनी किरकिरी का सामना करना पड़ेगा।

हरियाणा विधानसभा के चुनाव परिणामों से ऐसा प्रतीत होता है कि वहां भाजपा के पक्ष में पहले से ही अंडर कर्ट बह रहा था जिसे भांपने में कांग्रेस के रणनीतिकारों से चक हो गई। इसमें कई सदृश अभियान बल्कि वे निकलीं। उनके लिए यह आना पड़ा पूर्व मुख्यमंत्री

उनका हाथ मिलवाकर यह सदश देने की कोशिश तो जरूर की कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है परन्तु तब तक काफी देर हो चुकी थी। पार्टी के चुनाव अभियान से कुमारी शैलजा की इस दूरी ने पार्टी की चुनावी संभावनाओं को बहुत प्रभावित किया। टिकट वितरण में भूपिंदर सिंह हुड्डा ने जिस अपना वर्चस्व कायम रखा उसने भी अनेक नेताओं को रुष्ट कर दिया। कुमारी शैलजा की नाराजगी ने दलित वोट बैंक को पार्टी से दूर करने में बड़ी भूमिका निभाई। कांग्रेस ने यह खुशफहमी भी पाल रखी थी हरियाणा में किसानों की नाराजगी, अग्निवीर योजना का कथित विरोध, एंटी इन्कमबैंसी जैसे कारक उसका सत्ता से एक दशक पुराना वनवास समाप्त कराने में मददगार साबित होंगे परंतु शायद वह इस हकीकत को भूल गई कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की करिश्माई लोकप्रियता को चुनावी देने की स्थिति तक पहुंचना उसके लिए अभी नामुकिन ही है।
(त्रिपल सार्वजनिक विशेषज्ञ है)

टैगोर से दूर जाता बांग्लादेश



सा ही हो रहा है। वहाँ स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ने वाले और उसका विरोध करने वाले एक साथ मिल रहे हैं। देश के राष्ट्रगान को बदलन की मांग अब्दुल्लाहिल अमान आजमी भी कर रहे हैं। उनके पिता बांग्लादेश की जमाते ए इस्लामी पार्टी के शिखर नेता थे। उन्हें स्वाधीनता आंदोलन के समय पाकिस्तान सेना का साथ देने के कारण फारसी दे दी गई थी। उनके अलावा भी बांग्लादेश में बहुत से असरदार लोगों का कहना है कि उनके देश में एक हिन्दू के लिखे गीत को राष्ट्रगीत के रूप में थोपा गया। इसे बदला जाना ही चाहिए। इस तरह की मांग करने वालों में कर्नल ओ. अहमद और कर्नल राशिद चौधरी भी शामिल हैं, जो देश के संस्थापक मुजीब उल रहमान की 1975 में हुई हत्या की साजिश में दोषी ठहराए गए थे। वह दोनों अब कनाडा में रह रहे हैं।

गुरुदेव टैगेर को हिन्दू कवि कहने वाले अज्ञानी भूल रहे हैं कि वे मूल रूप से पर्वी बंगल से ही थे जो अब बांग्लादेश बन गया है और उनके परिवार की वहाँ प्रचुर संपत्तियाँ थीं। बांग्लादेश में काजी नजरुल इस्लाम जैसे महान बांग्ला कवि को भी खारिज किया जा है क्योंकि उन्होंने हिन्दू देवी-देवताओं की स्तुति में लिखा है। बांग्लादेश में ऐसे गीत की मांग हो रही है जिसमें 'दूसरी स्वतंत्रता' का उल्लेख हो। बांग्लादेश

में यूएनआई न्यूज एजेंसी के संवादद्याता के रूप में काम कर चुके बरिष्ठ पत्रकार और संपादक महेन्द्र वेद बताते हैं कि बांग्लादेश में राष्ट्रगान बदलने की मांग शेख मुजीब की अगस्त 1975 की हत्या के तुरंत भी बाद शुरू हुई थी। राष्ट्रपति खोंडकर मशताक अहमद ने एक समिति का गठन किया जिसने राष्ट्रगान को काजी नजरुल इस्लाम या फ़ारूख अहमद के लिये गीतों से से बदलने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि, उस वर्ष नवंबर में खोंडकर के हटाए जाने के बाद यह पहल पूरी नहीं हुई।

राष्ट्रपति जिया उर रहमान के नेतृत्व में, 'राष्ट्रवादियों' ने 'एक अधिक बांग्लादेश-केंद्रित राष्ट्रगान' को अपनाने की मांग की। 1979 में, कैबिनेट को भेजे गए एक पत्र में, तत्कालीन प्रधान मंत्री शाह अजीजुर रहमान, जो मुस्लिम लीग के पूर्व नेता थे, ने तर्क दिया कि अमार सोनार बांग्ला 'राष्ट्रीय पहचान और संस्कृति के विपरीत' है व्योंगि इसे 'एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखा गया था जिसकी गैर-बांग्लादेशी पृष्ठभूमि थी।' उन्होंने 'प्रथम बांग्लादेश' का प्रस्ताव रखा। जिया के राष्ट्रपति पद के दौरान, राष्ट्रीय टेलीविजन और सरकारी कार्यक्रमों के दौरान 'अमार सोनार बांग्ला' के बाद यह गीत बजाया जाता था। 1981 में जिया की हत्या के बाद यह बंद हो गया। यह गीत वर्तमान में जिया की

बांग्लादेश नेशनल पार्टी (बीएनपी) का 'पार्टी गीत' है।

जिया की पत्नी बेगम खालिदा जिया 2002 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थीं जब बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के नेता मोतीउर रहमान निजामी ने 'इस्लामी मूल्यों और भावना' को शामिल करने के लिए टैगेर के गीत में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि देश कि कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। बहरहाल, बांग्लादेश के संस्थापक नेता शेख मुजीब की मर्तियाँ नष्ट कर दी गईं और पाकिस्तान के संस्थापक महम्मद अली जिन्ना की पुण्यतिथि मनाई गई। बहुत साफ है कि बांग्लादेश अब बदल रहा है। उस पर कठमुल्लों का असर

बहुता जा रहा है। अब बांग्लादेश उस पाकिस्तान के करीब आ रहा है जिसकी सेना ने इस्ट पाकिस्तान में भयंकर कल्पे आम किया था। बांग्लादेश में 1971 में हिन्दुओं पर पाकिस्तानी सेनाओं का कहर टूटा था। उस समय खुलना, खुसिया, इसर्दीह आदि स्थानों पर क्या नरसंहार हुआ, क्या तबाही का आलम था, एक बुद्ध संवाददाता के रूप में उसका प्रत्यक्षदर्शी गवाह स्वयं मैं हूँ। न्यूयार्क टाइम्स ने अपनी 29 जून, 1971 की एक लोमधर्षक रिपोर्ट में पूर्वी पाकिस्तान के शहर फरीदपुर में सेना के आतंक की कहानी बचानी की थी। पाकिस्तानी सेना ने फरीदपुर में हिन्दुओं की दुकानों पर बड़े पीले रंग से 'एच' लिख दिया था जिन्हें सेना ने लूटना था। जाहिर है, 'एच' का मतलब हिन्दुओं की दुकानों से था। फरीदपुर के दस हजार हिन्दुओं में से अधिकतर की हत्या कर दी गई थी और बचे-खुचे भारत में जान बचा कर चले गए थे। दरअसल 1971 में पाकिस्तानी फौजों ने फरीदपुर ही नहीं, बल्कि सारे पूर्वी बंगल में हिन्दुओं को मारा था। पाकिस्तानी सेना पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं का नामोनिशान मिटाने पर लगी हुई थी। अब ये सवाल नहीं है कि जब भारत का बंटवारा हुआ था, उस समय पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) में हिन्दू वर्हा की आवादी के 30 से 35 फीसदी के बीच थे या अधिक। यह सवाल भी नहीं है कि क्या बांग्लादेश हिन्दू-विहीन हो जाएगा और वहां से मुख्देव टैगेर के लिखे राष्ट्र गीत को खत्म कर दिया जाएगा?

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्टंभकार और पूर्व सांसद हैं)

